'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 31.10.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 23 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 16 से 31 अक्टूबर, 2017

निजी क्षेत्र में आरक्षण का फायदा

डॉ. उदित राज

नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राजीव कुमार ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा वक्तव्य क्यों आया? ये तो वही जान सकते हैं लेकिन ये कोई जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं कि इनके सामने ऐसी मांग रखी गयी थी। हम उनसे तर्क करने के लिए तैयार हैं कि वे यह सिद्ध कर दें कि आरक्षण से अर्थव्यवस्था एवं विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हम आरक्षण की मांग इसलिए करते हैं कि भागीदारी का अवसर मिले और भेदभाव की नीयत से छुटकारा प्राप्त कर सके। अवसर ही योग्यता है। जिन्हें हजारों वर्षो से पढ़ने-लिखने का अवसर मिला ही न हो, उन्हें आरक्षण के माध्यम से अवसर प्रदान किया जाता है। आरक्षण का स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि हजारों वर्षो का पिछड़ापन एक और दो पीढ़ी में मिट जा पा रहा है।

ज्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों पर दलितों और पिछड़ों की भागीदारी है ही नहीं तो पिछड़ेपन और कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए आरक्षित वर्ग के लोग जिम्मेदार कहां से हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में 95 प्रतिशत से अधिक जज तथाकथित सवर्ण समाज से हैं, अगर निष्पक्षता से देखा जाए तो सबसे ज्यादा निकम्मापन यहीं पर है। 2 से 3 पीढ़ी तक मुकदमे चल रहे हैं। गरीबों को न्याय मिल नहीं पा रहा है और करोड़ों मामले निबटाने के लिए लंबित हैं। अखबार और चैनल में सवर्णो की ही भागीदारी है। सभी जानते हैं कि मीडिया समाज के निर्माण, शिक्षा, पारदर्शिता आदि के मामले में कहां खड़ी है। योगेन्द्र यादव और अनिल चमड़िया के द्वारा सीएसडीएस व मीडिया स्टडी ग्रुप के तहत वर्ष 2006 में बड़े 37 मीडिया संस्थानों में दलित भागीदारी को लेकर कराए सर्वे में हकीकत बयां करने वाले तथ्य सामने आए। सर्वे में राजधानी दिल्ली के किसी भी मीडिया संस्थान के निर्णायक शीर्ष दस पदों पर कोई दलित नहीं मिला। इसके मुताबिक ऊंची जातियों का मीडिया संस्थानों में 71 प्रतिशत शीर्ष पदों पर कब्जा है। इसमें 49 प्रतिशत ब्राह्मण, 14 प्रतिशत कायस्थ, 7-7 प्रतिशत वैश्य और राजपूत, खत्री 9 प्रतिशत, गैर द्विज उच्च जाति 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ी जाति 4 प्रतिशत हैं। इनमें दलितों की हिस्सेदारी कहीं नहीं दिखती।

तो वित्त, टैक्स, उत्पादन और गुणवत्ता आदि की कितनी खस्ता हालत है, क्या किसी से छुपा है। एक या दो भी मौलिक तकनीक का आविष्कार क्या हमारे निजी क्षेत्र ने किया है, जैसे कि बिलगेट्स ने विंडोज, जुकरबर्ग ने फेसबुक, स्टीव जॉन ने एप्पल और हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कार जैसी तकनीक बनाया। लगभग 95 प्रतिशत तकनीक आयातित है और शेष हमारी सरकार करती है। विकसित देशों में मुख्य रूप से तकनीक का आविष्कार निजी क्षेत्र ने किया। और उसका एक कारण यह है कि उनकी सोच में उदारता। नौकरशाही के शीर्ष पर शतप्रतिशत तथाकथित सवर्ण हैं और यदि भ्रष्टाचार, गुणवत्ता, कार्य में विलंबता और कानून-व्यवस्था की समस्या है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसी तरीके से ज्ञान-विज्ञान, तकनीक एवं चिकित्सा जैसी संस्थाओं में भी लगभग पूरा नियंत्रण इन्हीं के पास है। यदि आई. आई.टी. का इंजीनियर बाहर जाकर अच्छी नौकरी पा लेता है तो एक शिक्षित मजदूर के सिवाय क्या है?

आरक्षण जहां पहले सरकार में लागू हुआ, वहां न केवल प्रशासन ठीक रहा है बल्कि उन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य औद्योगिक विकास, प्रतिव्यक्ति आय और कानून व्यवस्था आदि सभी बेहतर रहे हैं। 1902 में कोल्हापुर की रियासत में शाहूजी महाराज ने 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया तो तुलना करें उत्तर भारत के राज्यों से तो पाएंगें कि महाराष्ट्र आगे मिलेगा। 1921 में तमिलनाडु में आरक्षण लागू हुआ, 1935 में त्रावणकोर की रियासत केरल में और इसी वर्ष में मैसूर की रियासत में लागू हुआ। शेष राज्यों में आरक्षण पूनापैक्ट या आजाद भारत के बाद लागू हुआ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राजीव कुमार को इसका अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद मेरा विश्वास है कि पूर्वाग्रहित नहीं होगें तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की पैरवी स्वयं करेगें। जो लोग योग्यता और दक्षता की बात करते हैं उन्हें हाल में हुए एक व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष को जान लेना चाहिए। दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स के प्रो. अश्विनी देशपांडे एवं मिशिगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक प्रो. थामस विसकॉफ ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण देने के कारण भारतीय रेलवे में 1980 एवं 2002 की अवधि का अध्ययन किया। यह रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल में भी छपी। भारतीय रेलवे पूरे विश्व में सबसे अधिक नौकरी देने वाला निकाय है, जहां पर आरक्षण लागू है। रेलवे में ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक में लगभग 13 से 14 लाख लोग काम करते हैं। 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं 7.5 प्रतिशत जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। इस अध्ययन ने पाया कि ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अधिकारी आरक्षण के कारण ही इन पदों पर पहुंच सके हैं। प्रो. देशपांडे एवं प्रो. विसकॉफ ने उन जोनों की तुलना की जिनमें सबसे अधिक और सबसे कम दलित कर्मचारी कार्यरत थे। उन्होंने पाया कि दोनों जोनों में कार्यक्षमता और उत्पादकता में कोई अंतर नहीं है, उल्टे उन्होंने पाया कि कुछ जोन जिनमें दलित कर्मचारी ज्यादा थे, वहां उत्पादकता अधिक बढ़ी।

उपरोक्त उदाहरण भारतीय परिप्रेक्ष्य के हैं, जो आरक्षण के पक्ष में जाते हैं। मलेशिया में किसी भी ब्ल्यू चिप कंपनी के 30 प्रतिशत शेयर वहां के भूमिपुत्र, जो दलितों और पिछड़ों के समकक्ष हैं, के मालिक होते हैं। व्यापार, उद्योग आदि में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार का एक फंड जो इन लोगों के लिए कंपनियों का डिवेंचर खरीद देती है, डिवेंचर पर कंपनियां ब्याज देती हैं जो इनके नियमित आय का स्रोत होता है। डिवेंचर इसलिए कि अगर कंपनी का घाटा हो तो भी डिवेंचर धारकों को उनका पैसा लौटाना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट की टीम में कम से कम छः अश्वेत का होना जरूरी है। क्या वहां की क्रिकेट की टीम किसी से खराब है। अमेरिका में आरक्षण का पर्याय अफर्मेटिव एक्शन है और लगभग सभी निजी क्षेत्र के व्यापार, कंपनी, मीडिया व संस्थाएं अश्वेतों को अवसर देती हैं। वहां के अश्वेत यहां के दलितों व पिछड़ों के समकक्ष हैं।

कहना चाहता हूं कि वे आरक्षण का स्वागत करें, इससे उनका भला ज्यादा होगा, दलितों व पिछड़ों का कम। इनकी आबादी सबसे ज्यादा है और निजी क्षेत्र में इनको भागीदारी देने का मतलब कि इनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी और इससे तथाकथित सवर्णो की कंपनियों और उद्योगों का ही फायदा होगा, क्योंकि सामान उन्हीं का बिकेगा। जब दलितों और पिछड़ों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो इनमें शिक्षा भी बढ़ेगी। बिना देश को शिक्षित किए भारत कभी भी विकसित देश नहीं हो सकता। इनकी भागीदारी से सामाजिक सौहार्द्र बनेगा और जात-पांत की जो खटास है, कम होगी। जिसकी आय और शिक्षा दोनो अच्छी होती है, वह कानून-व्यवस्था बनाने में सहयोगी होता है और स्वच्छ बनाने में भी मदद। नेता लोग जाति के नाम से पिछड़ेपन या भेदभाव के घाव को कुरेदकर गोलबंदी आसानी से नहीं कर पाएंगें और विकास और स्वच्छ प्रशासन इत्यादि के नाम से चुनाव भी होगें। अगर भेदभाव वाली मानसिकता आड़े न आए तो सवर्ण भी निजी क्षेत्र में आरक्षण की पैरवी करेगें।

परिसंघ की रैली

4 दिसंबर,2017 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की 20वीं महारैली आगामी 4 दिसंबर, 2017 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इसकी सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री 'वॉयस ऑफ बुद्धा' सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करा लें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook.com/aiparisangh पेज को लाइक करें, ट्विट्र @aiparisangh को फॉलो करें और www.vobnews 24.com भी देखें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

म.प्र. परिसंघ का कार्यकर्त्ता सम्मेलन संपन्न

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ, मध्य प्रदेश, द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक दिवसीय प्रदेश कार्यकर्त्ता सम्मेलन का आयोजन 29 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक गांधी भवन, पालिटेक्निक चौराहा, भोपाल म. प्र. में खचा-खच हाल से भरे पदाधिकारियों की उपस्थित में सम्पन्न हुआ।

मंच पर डॉ. उदित राज के साथ नरेन्द्र चौधरी एवं परमहंस प्रसाद

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज उपस्थित थे। सभाध्य के रूप में म.प्र. परिसंघ के अध्यक्ष. मा. परमहंस प्रसाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में परिसंघ महिला मोर्चा की सह संयोजिका कुमारी अर्चना भोयर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय राज, छतरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश प्रजापति, देवेश कल्याणी-संपादक सान्ध्य दैनिक प्रदेश टुडे भोपल ,म.प्र. के कार्यवाहक अध्यक्ष मा. बिपिन टोपो, डॉ. जगदीस सूर्यवंशी, ओ. पी. अहिरवार, जे. पी. ननहट बौद्ध, एच.आर. चौहान, नरेद्र चौधरी, प्रदेश महासचिव, एफ.एस. बरैया, डॉ. के. के. बच्चन, लक्ष्मन सिंह शिलोटे, रजनी कल्याणी आशीष कुमार, बी. एल. हरोर, मोहन खोड़े, के. के. बन्जारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, के. के. जोशी, दयाशंकर, दयाराम, बी. एल. चौधरी, तुलसी राम, इं. बिनोद बट्टी, महिला पदाधिकारी के रूप मे सुधा देवी, लक्ष्मी सिंह, के अलावा जिला एवं सम्भाग के पदाधिकारियों ने प्रदेश सम्मेलन को संबोधित किया।

कार्यकर्त्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में मध्य प्रदेश की संख्या अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर द्वारा यदि आरक्षण का प्रावधान न किया गया होता तो आज भी हमारी दुर्दशा इससे कहीं ज्यादा होती। अब चूंकि ज्यादातर विभागों का निजीकरण किया जा रहा है तो यदि आरक्षण की लड़ाई कमजोर हाती है तो हम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगें। उन्होंने कहा कि साल के 365 दिनों में सिर्फ एक दिन आरक्षण बचाने की लड़ाई के लिए मांगा जा रहा है, यदि वह भी नहीं मिल सकता तो हमारे अधिकार छिनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील किया कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सोसल मीडिया का इस्तेमाल करें और परिसंघ का फेसबुक पेज लाइक करें और ट्वीटर पर फालो करें। परिसंघ के यूट्यूब चैनल को सब्सिक्राइब करें। VOB New 24 चैनल मुख्य रूप से परिसंघ की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए बनाया गया है, उसे सब्सिक्राइब करें। अब परिसंघ की बेबसाइट www.aiparisangh.com पर ऑनलाइन वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बनाने का प्रावधान कर दिया गया है। बेबसाइट पर जाकर सदस्य बनें और ऑनलाइन डोनेशन भी करें। उन्होंने बताया कि आगामी 5 नवंबर को परिसंघ के प्रमुख पदाधिकारियों एवं VOB New 24 चैनल टीम की एक बैठक स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली पर रखी गयी है, जिसमें रैली की सफलता की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और प्रचार सामाग्री भी वितरित की जाएगी। इसलिए परिसंघ के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारी 5 नवंबर को प्रातः 10 बजे इस बैठक में शामिल हों।

प्रदेश अध्यक्ष, श्री परम हंस प्रसाद जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज जी को आश्वासन देते हुए कहा कि इस बार दिल्ली में 4 दिसंबर की रैली में मध्य प्रदेश की अच्छी भूमिका रहेगी।

दीए जलाने का रिकॉर्ड एक बच्ची के खाली पेट मर जाने से ज्यादा ध्यान खींचता है

हम भूख को क्यों नहीं पहचान पाते

उर्मिलेश

ठोस तथ्यों और आंकड़ों के बावजूद भारत की मध्य और उच्चवर्गीय आबादी का बड़ा हिस्सा अपने समाज में चारों तरफ फैली भूख, बेहाली और लाचारी को नजरअंदाज करते रहने में ही अपनी भलाई समझता है। आर्थिक सुधारों के बाद के दौर में गरीब और अमीर के बीच की दूरी सिर्फ भौतिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक स्तर पर भी बढ़ी है। हम लोगों के जीवन में छाया अंधेरा नहीं देखना चाहते। कभी हम नदी किनारे दीप जलाकर 'रिकॉर्ड' बनाते हैं तो कहीं किसी निर्माणाधीन मूर्ति या पुल को दुनिया की सबसे ऊंची या लंबी बताकर खुश हो लेते हैं। ऐसे दावे असल में उन ठोस वैश्विक सच्चाइयों से कतराने की कोशिश हुआ करते हैं, जो हर साल दुनिया के तमाम विकास संबंधी सूचकांकों में साफ-साफ झलकती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट' से 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' जारी हुआ तो जमीनी स्तर पर भारत की बदहाली को लेकर जैसी चिंता दिखनी चाहिए थी, वह हमारे समाज, सियासत और मीडिया में नहीं दिखी। उस वक्त तो देश का ज्यादातर मीडिया किसी हनीप्रीत की तलाश में या राधे मां के थानेदार की कुर्सी पर बैठने की कहानी में उलझा हुआ था।

खबरों का खेल

119 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत के 100 वें स्थान पर होने की खौफनाक असलियत का ठोस सबूत अब झारखंड के सिमडेगा जिले की 11 वर्षीय बच्ची संतोषी की मौत के रूप में सामने आया है। भूख से मौत हमारे मुल्क के लिए कोई नई बात नहीं है। देश के अनेक हिस्सों में गरीब लोग भूख और साधारण बीमारियों से मरते रहते हैं पर वे खबर नहीं बनते। बहुत दिनों बाद किसी के भूख से मरने की खबर हमारे मीडिया में आई है, लेकिन इस पर खास चर्चा नहीं हुई। अयोध्या के सरयू तट पर लाख दीयों की जगमग दिवाली की खबर अखबार से लेकर चैनलों तक छाई रही। मिथकों पर भरोसा करें तो वनवास से लौटे राम के लिये अयोध्या में आम जन ने दीप जलाए और पुष्पवर्षा की। पर इक्कीसवीं सदी में यह सब सरकारी स्तर पर हुआ। सरकारी पैसे से सरयू तट पर 1 लाख 87 हजार 213 दीये जलाये गए, वह भी दीवाली से एक दिन पहले। सरकारी हेलिकाप्टरों से पुष्पवर्षा की गई। टीवी चैनल इसे घंटों लाइव दिखाते रहे। पर इनकी स्क्रीन पर कहीं भी झारखंड की 11 वर्षीय संतोषी की मौत की खबर नहीं थी।

अखबारों-वेबसाइटों में भी यह खबर बीस दिन बाद छपी, पर इसने हमारे विकास के मॉडल, राजनेताओं के सत्ता-प्रपंच और योजनाकारों की प्राथमिकता की पोल खोलकर रख दी। महानगरों के बड़े संस्थानों और दफ्तरों में ऊंची कुर्सियों पर बैठे जिन लोगों को यकीन नहीं था कि भारत जैसे 'तेजी से विकसित होते देश' में लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, उनके लिये यह खबर चौंकाने वाली थी! झारखंड में जिस दिन यह मामला सामने आया, उसी दिन से सत्ताधारियों का एक हिस्सा संतोषी की मौत को मलेरिया और भूख के विवाद में उलझाने में लगा है। बहरहाल, उनके अपने उलझाव के बीच इस बात का भी रहस्योद्घाटन हो गया कि 'आधार कार्ड' की अनिवार्यता कैसे गरीबों की मौत का कारण बन सकती है। संतोषी के घर वालों का राशनकार्ड आधार से लिंक नहीं हो पाया तो जन-वितरण विभाग ने उनके राशनकार्ड को ही निरस्त कर दिया। इससे परिवार को कई महीने से राशन नहीं मिल पा रहा था।

> झारखंड में जिस दिन संतोषी की मौत की खबर आई, उसी दिन से सत्ताधारियों का एक हिस्सा इसे मलेरिया और भूख के विवाद में उलझाए पड़ा है

वैश्विक भूख सूचकांक की तरह एक और ग्लोबल इंडेक्स भारत के संदर्भ में बहुत डरावना है। वैश्विक असमानता सूचकांक में भारत इस वक्त दुनिया के 180 मुल्कों में 135वें स्थान पर है। मानव विकास आंकने वाले 180 देशों के वैश्विक सूचकांक में भारत इस वक्त 130 वें स्थान पर है। यानी हमारे यहां 'आर्थिक विकास', 'ग्रोथ रेट' और तमाम तरह के कर-सुधारों का लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग खूब तरक्की कर रहे हैं जबकि बहुत सारे लोग बेहाल हो रहे हैं। इससे असमानता तेजी से बढ़ रही है। पता नहीं क्यों अपने देश के अमीर लोग इस स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं नजर आते। वे क्यों नहीं सोचते कि दुनिया उन्हें 'भुक्खड़ों और बर्बाद लोगों के महादेश' का 'अमीर' मानती है। वे अपने इस निजी और राष्ट्रीय-अपमान से आहत क्यों नहीं होते। दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल इलाका कहलाने वाले यूरोप में कौन सा ऐसा देश होगा, जहां भारत की तरह सिर्फ 1 फीसदी लोग पूरे मुल्क की 58 फीसदी संपदा के मालिक हों और 10 फीसदी लोग देश की लगभग 80 फीसदी संपदा पर काबिज हों। इससे भारत में तेजी से बढ़ती गैर-बराबरी का अंदाजा अच्छी तरह लगाया जा सकता है। पर हमारे योजनाकारों के लिये यह चिंता का सबब नहीं है।

चमकीले दावे

वे तरक्की के लिये कभी विनिवेश पर जोर देते हैं, तो कभी 'कर-प्रणाली में बड़े सुधार' का ऐलान करते हैं। कभी 'मनरेगा' जैसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करते हैं तो कभी कोई 'उज्ज्वला' योजना लाते हैं! तरक्की को ज्यादा चमकीला दिखाने के लिए कभी सवा लाख करोड़ की 'बुलेट ट्रेन' का प्रस्ताव लाते हैं तो कभी एक साथ सौ से अधिक सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं। लेकिन मानव विकास की स्थिति सुधारने या असमानता की समस्या को संबोधित करने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाते! यह स्थिति हमारे गणतंत्र के लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम 'मंदिर-मस्जिद', 'लव जिहाद' और गौरक्षा के नाम पर समाज में परस्पर विद्वेष बढ़ाने के बजाय सबके लिए समान शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर लाएं तो रास्ता मिल सकता है। लेकिन कोई सुनने को तैयार है क्या? दीए जलाने का रिकॉर्ड एक बच्ची के खाली पेट मर जाने से ज्यादा ध्यान खींचता है।

http://epaper.navbharattimes.com/details/35231-63345-1.html

माहवारी से गुजरती हैं महिलाएं, नियम चलते हैं पुरुषों के

आरती रानी प्रजापति

महावारी 10–14 की आयु में शुरु होने वाला नियमित चक्र है। जिसमें स्त्री की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। यह वह समय है जब स्त्री के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। महावारी सिर्फ शरीर में घट रही एक घटना नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध दिमाग से भी है। महावारी के समय स्त्री थकान महसूस करती है। लगातार 3–4 दिन का रक्त स्त्राव उसे कमजोर करता है। कई महिलाओं को इस समय हाथ–पैरों में सूजन, पेट–पैर में दर्द, कमर दर्द, बुखार, भूख न लगना, कब्ज, चिड़चिड़ापन, उल्टी, चक्कर आना जैसी अन्य समस्याएँ भी होती हैं। कुल मिलाकर महावारी के समय स्त्री का स्वास्थ देखभाल की मांग करता है उसे आराम की जरूरत होती है जिसे अति संवेदनशील पितृसत्तात्मक समाज नहीं समझता। स्त्री के इस प्राकृतिक नियम को समाज उसकी कमजोरी मानता है।

आज जब हम फोर–जी के जमाने में जी रहे हैं तब भी कई भारतीय घरों में माहवारी के समय महिलाओं से काफी भेद भाव किया जाता है। महावारी के समय अक्सर घर की सभी चीजों को उस महिला से दूर रखा जाता है। वह चीजें यदि ईश्वर से जुड़ी हों तो उसको महिला छू भी नहीं सकती। आज भी ऐसे बहुत से भारतीय मंदिर है जिनमें महिला प्रवेश वर्जित है। कारण सिर्फ उसका स्त्री लिंग में जन्म। यदि स्त्री लिंग में जन्म ही बुरी चीज है, प्रत्येक मंदिर से देवियों की मूर्तियों को हटा देना चाहिए। क्योंकि वे भी महिला ही हैं जिन्हें कभी न कभी महीना आता ही होगा। यदि नहीं आता तो वे माँ क्यों कहलाती हैं? जिन देवी को हम माँ कहकर पुकारते हैं वह भी महीने के उन दिनों में हमें अछूत घोषित कर देती हैं।

महावारी में ऐसा क्या है जो इसे इतना घृणित माना जाता है। क्या रक्त का निकलना वास्तव में एक अपराध है? नहीं! माहवारी में पवित्रता की यह जो धारणा है उसका सीधा सम्बन्ध स्त्री की योनि से है। रक्त का स्राव योनि से होता है इसलिये माहवारी के रक्त को अपवित्र माना गया है। वरना शरीर के किसी अन्य अंग से निकले रक्त की तरह ही यह भी रक्त ही है।

महावारी लड़की को, दरअसल, कम करके आंकने का एक तरीका है। स्त्री को बार–बार समाज यह बोध करवाता है कि तुम पुरुष से कम हो। स्त्री को दोयम दर्जे पर रखने का यह सरल उपाय है। पुरुष को किसी तरह के स्राव को झेलना नहीं पड़ता। स्त्री को महावरी होती है इसलिए वह निम्न दर्जे की प्राणी है। सभ्यता के साथ साथ स्त्री के मन में भी इस बात को इस तरह बैठा दिया गया है कि वह महावारी में खुद को अछूत मानने लगती है। वर्ण–व्यवस्था में अछूत उस तबके को माना गया जो सबसे ज्यादा काम करता है। यही हाल स्त्री के साथ भी है। स्त्री की हालत कहीं–कहीं दलितों से भी खराब है। दोनों (स्त्री और दलित) को इनकी स्थिति के लिए पूर्व जन्म के कर्मो को दोषी बना दिया जाता है। स्त्री को कम करके आंकने पर ही पुरुष वर्चस्व स्थापित हो सकता है। वरना महावारी एक नियमित चक्र है। जिसे सोना, खाना, पीना के अनुसार ही लेना चाहिए। क्योंकि यह रक्त स्त्री की योनि से निकल रहा है इसलिए इसे अपवित्र, घटिया माना गया। यानी स्त्री की योनि एक खराब अंग है। अंग स्त्री का है इसलिए कुल मिलाकर स्त्री ही खराब है। स्त्री को दोयम दर्जे पर रखने के लिए कोई ऐसा साधन चाहिए था जो पुरुष से अलग हो। गर्भ धारण भी पुरुष से अलग ही प्रक्रिया है। पर उसको यदि हीन नजर से देखें तो विवाद हो जाएगा। क्योंकि गर्भ पुरुष के वीर्य से बना है। इसलिए यदि स्त्री गर्भ धारण करती है। तो उसको अपवित्र नही माना जाता, लेकिन रजस्वला स्त्री अपवित्र की कैटेगीरी में रखी गई। गर्भ का संचार पुरुष योग से हुआ है इसलिए तभी तक वह सही है जब तक प्रसव नहीं हुआ। ध्यान रहे प्रसव के बाद भी स्त्री के साथ अछूत जैसा ही व्यवहार किया जाता है। जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ हो कुछ समय बाद तक वह अशुद्ध ही रहता है। और उसके शुद्धिकरण के लिए हवण आदि करवाया जाता है। यानी अपवित्र स्त्री को धर्म ही पवित्र कर सकता है। उससे इतर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो स्त्री को अछूत होने से बचा सके। अजीब बात है कि हम सभी स्त्रियाँ इस स्त्री विरोधी मानासिकता को न सिर्फ झेल रही हैं बल्कि आगे भी बढ़ा रही हैं।

पहले के समय में महीने के इन दिनों में कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था। महिला को यह समझने का मौका ही नहीं दिया जाता कि उसका शरीर जरुरी है। घर की पुरानी चादर, फटे कपड़े महीने के इन दिनों के लिए रखे जाते थे। पहले पेड की भी सुविधा नहीं थी। फलस्वरूप महिला राख, मैले कपड़े, फटी चादरों को धो–धो इस्तेमाल करती थी। जिस कारण महिलाओं को योनि से सम्बंधित कई बीमारियाँ हो जाती थी। आज के समय में ऐसी महिलायें कम नहीं जिन्हें डॉक्टर से अपनी बात कहने में शर्म आती हो। पहले ऐसे डॉक्टर भी मिल पाना कहाँ संभव था। चिकित्सा की सुविधा भी एक वर्ग तक सीमित रही है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की क्या दशा है यह गोरखपुर हत्याकांड से साबित हो जाता है।

पैड भले ही मामूली चीज लगे लेकिन यह हर महिला के लिए जरुरी वस्तु है जिस पर सरकार द्वारा टैक्स महिला के उन दिनों की समस्या को बढ़ाना है। भारत जैसे गरीब देश में जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं वहां महिलाओं को आज भी कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन क्षेत्रों में पैड एक विलासिता की वस्तु के रूप में देखा जाता है। सरकार को चाहिये कि इस वस्तु पर लगे टैक्स को न सिर्फ कम करे बल्कि इसके दाम भी कम करे। जिससे हर घर की महिला इस विलासिता माने जाने वाली चीज का इस्तेमाल कर सके। एक पैड भले ही मामूली लगे पर यह स्त्री को बाहर आने जाने में सहूलियत देता है। आप कहीं भी उठ–बैठ सकती हैं। कपड़े में रक्त को सोखने की वह शक्ति नहीं होती। शुरुवाती दिनों में जब महिला को अत्याधिक रक्तस्राव होता है कपड़ा आधे घंटे भी नहीं टिक सकता। जबकि पैड आपको 10–12 घंटे की सुरक्षा प्रदान करता है।

सैनेटरी पैड कोई दिखावे की वस्तु नहीं न ही श्रृंगार का सामान है। यह ऐसी वस्तु नहीं जिसके कारण महिला की जिन्दगी प्रभावित न होती हो। जहाँ सुविधा नहीं है वहां लड़कियाँ महीने के उन दिनों में पढाई छोड़ घर पर बैठ जाती है। भले ही आप कहें कि रोज लाखों पैड बिकते हैं उसपर टैक्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करे न करे, लड़कियों को जो किसी तरह एक पैकेट पैड खरीद पाती थी उन्हें घर में बंद जरुर करेगा। फिर आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या होगा? भई, जिसके पास पैसा है वह चीजों के दाम बढ़ जाने पर भी इतना विचलित नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा खर्च कर सकने की हैसियत रखते हैं। सरकार का यह कदम गरीब महिला के स्वास्थ्य के लिए कितना घातक होगा यह आने वाली खबरें ही तय कर देंगी।

http://hindi-roundtableindia-co-in//index.php/perspective/gender/8805-माहवारी-से-गुज़रती-हैं-महिलाएं%2 C -नियम-चलते-हैं-पुरुषों-के

***

अखिल भारतीय परिसंघ के दो दिवसीय सम्मेलन मे महिला प्रकोष्ठ की भागीदारी

दिनांक 30सितंबर व 01 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर हाल में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सकुशल सम्पन्न हुआ। जिसके प्रथम दिन के प्रातः प्रहर में संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज जी ने दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर व तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित किए व एक लंबी अवधि का उदबोधन देकर कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। और लोगों को अपनी सोच समस्त आडम्बरों को त्याग कर वैज्ञानिक तार्किक रखने की सख्त हिदायत दी।। तथा भोजन के बाद के प्रहर में एक वेब न्यूज चैनल वॉइस ऑफ बुद्धा vobnews24.com का उदघाट्न किया। जिसके चौनल हेड श्री भरतलाल जी हैं। और उसके दस सदस्यीय बोर्ड में श्री राज जी ने अन्य प्रदेशाध्यक्षों सहित मंच से औरैया के श्री बलराम सिंह जी को सदस्य मनोनीत किया। और साथ ही इस दिन शाम को श्री राज जी ने 2 घण्टे : स्त्री समस्या और पुरुष प्रधान सोच पर एक बहस कराई जिस पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर पुरुषों की निरर्थक आपत्ति का बड़े ही तार्किक ढंग से डॉ. कुंजन जी ने खंडन किया व साथे महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती सविता कदियान पंवार जी ने भी अनेको महिलाओं को साथ आने का आह्वान किया व कहा कि पिछले कुछ समय से पूरे देश के अलग अलग कोनों में दलित महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और शर्मसार करने वाली घटनाओं की सख्या लगातार बढ़ती जा रही है आखिर कब तक दलित महिलाएं इस अत्याचार की पीड़ा सहेंगी ।महिला का सशक्तिकरण सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगा बल्कि उन्हें भी पुरुषों की तरह बाहर निकलना होगा। महिला को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। गार्मीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि महिलाएं चाहे दलित समाज की हो या सवर्ण समाज से सभी वर्ग की महिलाओं को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। सविता जी ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है यदि उनकी भागीदारी नहीं होगी तो देशा का विकास संभव नहीं हो सकता और जो महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं उनके लिए आज के सभय में जीवनयापन करना बेहद मुश्किल है उन्हें न कोई अधिकार दिया जाता है न ही पुरुषों के बराबर भागीदारी। ऐसे में हम सबको मिलकर अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सभी वंचित महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाने की जरुरत है । डॉ. उदित राज जी ने भी कहा कि कई देशों में गये है और वहा देखा है कि किस प्रकार महिलाओ की भागीदारी पुरुषों के बराबर है और कहीं कहीं तो पुरुषों से ज्यादा भागीदारी ज्यादा महिलाओं की देखी जाती हैं।

मंच पर डॉ. उदित राज जी के बाएं सविता कादियान पंवार राष्ट्रीय संयोजिका, दाएं अर्चना मौयर राष्ट्रीय सह संयोजिका एवं परिसंघ महिला प्रकोष्ठ की टीम

कार्यक्रम के दूसरे दिन के प्रातः प्रहर में श्री परमेन्द्र जी ने तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रशिक्षित कर लोगों को शांति पथ आष्टांगिक मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि ये सम्मेलन विजयादशमी के दिन आयोजित हुआ था। क्योंकि इसी दिन विश्व रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी। उसी अनुक्रम में करीब 1200 लोगों ने हजारों जातियों में बंटे धर्म का त्याग कर 22 प्रतिज्ञाओं का संकल्प लेते हुए आडम्बरी क्रियाकलापों से आजीवन दूर रहने का संकल्प लिया।

ततपश्चात द्वितीय प्रहर में दिसम्बर में आयोजित होने वाली रामलीला मैदान में 20वीं वार्षिक राष्ट्रीय महारैली की तैयारियों के सन्दर्भ मे सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से श्री राज जी ने प्रगति रिपोर्ट ली। जिसमें प्रदेश महासचिव श्री नीरज कुमार चक जी ने 5 लाख रुपये चन्दा तथा 1 लाख लोगों के साथ आने का वचन दिया।

इसी के बाद श्री राज जी ने कार्यक्रम का समापन भाषण देते हुए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।। जिसमें विशेष रूप से VOB NEWS 24 चैनल टीम एवं सोशल मीडिया सेल धन्यवाद के पात्र रहे।

– सविता कदियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ
मों. 9873944026

***

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

"अभी नहीं – तो कभी नहीं"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का

अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति हेतु

रैली

डॉ. उदित राज (Ex. IRS),
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

4 दिसंबर, 2017
सोमवार, सुबह 11 बजे
रामलीला मैदान, नई दिल्ली

AlParisangh
AlParisangh
9899766443
parisangh1997@gmail.com
All India Parisangh
www.aiparisangh.com

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

निवेदक : ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, देवी सिंह राणा, एन.डी. राम, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तमाने, संजय कांबले, अर्चना भोयर, सुनील जोडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता (हरियाणा), तस्सेम सिंह घारू, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), विजय राज अहिरवार, हीरा लाल (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. कसुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा, रेव लन्यू हिलेरी ए (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), Ch. दास (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.) पी. बाला (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विलिफ्रड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू (कर्नाटक), सीताराम बंसल, निहाल सिंह निहलता (हि.प्र.), प्रदीप बारफोर (असम)

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

आगामी रैली से संबधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

प्रमुख उपलब्धियां

1. तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया
2. लोकपाल में आरक्षण कराया
3. 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने
4. पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की
5. संसद में सबसे अधिक दलितमुद्दे उठाए
6. पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन

प्रमुख मुद्दे

1. पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण
2. आरक्षण कानून बनाओ
3. सेना और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण
4. सफाई काम में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना
5. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
6. समान शिक्षा एवं भूमिहीनों को भूमि
7. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
8. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
9. महंगाई की दर से छात्रवृति में बढ़ोत्तरी
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
11. जम्मू व कश्मीर में धारा 370 हटाया जाए और आरक्षण लागू हो

साथियो,

लोगों को यह लगता है कि पदोन्नति में आरक्षण भी समाप्त हो रहा है, उसको लेकर प्रभावित लोग कुछ चिंतित हैं। जो देख और महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वह यह कि सरकारी नौकरी लगभग समाप्ति की ओर है। कारण है आउट सोर्सिंग, ठेकेदारी, विनिवेश और एफ.डी.आई. आदि। जहां पहले हजारों की भर्ती की सूचना अखबारों में निकलती थी अब कभी-कभार दर्जनों में ही दिखती है। सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बी.एम.एल., सालेम स्टील प्लांट जैसी सरकारी कंपनियों को हाल ही में बेच दिया गया है, अब यहां आरक्षण खत्म। अभी 21 रेलवे स्टेशनों का निजीकरण हुआ और एअर इंडिया, जहां लाखों नौकरियां हैं, निजीकरण के रास्ते पर है। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने ही निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात सन् 2002 से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस में ला दिया था लेकिन आवश्यक सहयोग न होने की वजह से डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार जो कुछ करने वाली थी वह भी पूंजीपतियों के दबाव में रुक गया। ठेकेदारी का रास्ता निकालकर सरकारी नौकरी ही नहीं समाप्त की जा रही है, बल्कि आर्थिक शोषण भी तेज हो गया है। शिक्षा के निजीकरण की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव बढ़ा है, चाहे वह हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला का मामला हो या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय हो। जातीय पूर्वाग्रह के कारण ही सहारनपुर में भीम सेना ने जन्म लिया और दबंगों और दलितों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। वह ऐ जातीय व्यवस्था! तू हजारों वर्षों से सबसे गंदा काम दलितों से कराए और उसके करने पर भी हत्या और भेदभाव। ऐसे में कैसे देश महान हो सकता है ?

जब तक कुछ बातों पर विमर्श नहीं होता तब तक संघर्ष भी सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। पहला, विधायक, सांसद, मंत्री इसलिए नहीं लड़ेंगें, क्योंकि दलित का भी वोट इनके कहने से नहीं बल्कि राजनैतिक पार्टियों के प्रभाव से पड़ता है। जब एक दलित सांसद खुद के लिए दलित का वोट प्राप्त नहीं कर पाता तो वह क्या इनके लिए लड़ सकता है ? अगर ज्यादा दलित-प्रेम दिखाने की कोशिश करता है तो उसी के दूसरे या तीसरे भाई को खड़ा कर दिया जाता है। बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने यह जरूर कहा था कि राजनैतिक सत्ता से सारे ताले खुल जाते हैं। यह कथन सत्य है लेकिन वे खुद कांग्रेस में रहकर इतना कुछ कर गए, जबकि राजनैतिक सत्ता मेहरू जी के हाथ में थी। जिस तरह से जाट और पटेल समाज बिना नेताओं के सड़क पर उतरकर संघर्ष किया, वैसा ही करना पड़ेगा, वरना राजनैतिक सत्ता के इंतजार में सबकुछ खो बैठेंगें।

विधायिका और कार्यपालिका आरक्षण खत्म नहीं कर सकती इसलिए व्यायपालिका का सहारा लिया जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण की समस्या मध्य प्रदेश, उ0प्र0, जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों में पैदा होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जज का कहना है कि एक ड्राइवर और एक जज एक समान नहीं हो सकते। जबकि सच्चाई यह है कि एक समान हैं, अगर जाति एक है तो। ड्राइवर की जिंदगी कार ड्राइविंग सीट पर नहीं बीतती और जज की फाइल में नहीं, इंसाफ जिंदगी समाज में ही जीता है। एक जाति के ड्राइवर और जज भाई या बिरादरी होते हैं, जबकि दूसरी जाति का जज अछूत। इस तर्क के द्वारा व्यायपालिका दलित और आदिवासी आरक्षण में भी क्रीमीलेयर लाने का षड्यंत्र कर रही है।

यह अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का परिसंघ ही है, जो 5 आरक्षण विरोधी आदेश, जो 1997 में जारी हुए थे, के खिलाफ संघर्ष किया और 3 संवैधानिक संशोधन कराए। पिछड़ों के लिए मिले उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा। बहुजन लोकपाल बिल बनाकर लोकपाल में आरक्षण कराया। 2006 में पदोन्नति में आरक्षण के मुकदमे (नागराज) की पैरवी सरकार से 40 लाख रुपये दिलवाकर विजी वकील से कराई। डॉ. उदित राज ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश किया, जाट और मराठा जैसे सामाजिक आंदोलन का समर्थन मिला होता तो अब तक संसद कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाती। देश में परिसंघ ही एक ऐसी संस्था है, जो लाखों कर्मचारियों व अधिकारियों की समस्याओं के लिए पत्र लिखकर या टेलीफोन करके सहायता करता रहता है। 4 नवंबर, 2001 को लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। क्या देश में कोई अन्य ऐसी संस्था है जिसने अधिकार दिलाया हो और वैचारिक लड़ाई भी लड़ी हो। हां, कुछ संगठन हैं जो दुश्मन को गाली-गलौच देकर लोगों को एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन क्या मैदाने जंग में अधिकार लेने के लिए कभी आए। परिसंघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों में आगे है। हम तो कहते हैं कि परिसंघ से अच्छा कोई और संगठन हो तो उसका साथ दो नही तो जात-पांत, एवं अहंकार भूलकर 4 दिसंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में 11 बजे लाखों की संख्या में शामिल हों। याद रखें कि संख्या ही एक हमारी ताकत है। लाखों गोष्ठी और स्थानीय मीटिंगें कर ली जाएं तो उसका प्रभाव नहीं होने वाला है, जितना कि लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा होकर।

निवेदक : ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, देवी सिंह राणा, एन.डी. राम, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, अर्चना भोयर, सुशील जोडे (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता (हरियाणा), तरसेम सिंह घारू, रोहित सोनकर (पंजाब), विश्राम मीना, एम.एल. रासु, मुकेश मीना (राजस्थान), विजय राज अहिरवार, हीरा लाल (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, बरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुणइया, पी. एव. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा, रेव लब्धू हिलेरी ए (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तलंगाना), वैप दास (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.) पी. बाला (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान (बिहार), जे. श्रीनिवासलू (कर्नाटक), सीताराम बंसल, निहाल सिंह निहलता (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर (असम)

Major Achievements:

1. Saved Reservation by introducing 3 constitutional amendments
2. Secured Reservation in Lokpal
3. Lakhs of people adopted Buddhism on 04 th November, 2001
4. Raised issue of reservation in judiciary in the Supreme Court
5. Raise highest number of questions of Dalits in the Parliamnet
6. Support to reservation for OBCs in higher education

Major Issues :

1. Reservation in promotion and in private sector
2. Enact Reservation Act
4. Reservation in higher judiciary and armed forces
5. Ban recruitment on contract
6. Special recruitment drives to fill backlog posts
7. Free and Equal Education and land to the landless
8. Law for implementation of SCP and TSP
9. Caste certificates of one state made valid in all states
10. Increase in educational scholarships in line with price rise
11. All India Judicial Services to be implemented
12. Reservation in Jammu and Kashmir by removing Article 370

We, a few affected feel that reservation in promotion is real important issue but the real danger is not being perceived of erosion of government jobs which is being done under the garb of Outsourcing, Contract System, Disinvestment and FDI etc. There was a time when thousands of government jobs used to be advertised in the newspapers but now they are reduced to a few numbers. Central Electronics Limited, BEML, Salem Steel Plant like public sector undertakings have been privatized which means the death of reservation. Recently 21 railway stations were privatized and one of the largest government company that is Air India is on the verge of privatization. The All India Confederation Of SC/ST Organization is the one which raised the issue of reservation in private sector from the year 2002 onwards and that eventually became a national issue. The UPA government was pressurized to do something in this direction but due to weak mass support in our side , it was scuttled. The contract system is not only killing the jobs in the government but also increasing economic exploitation of workers. The privatization in education has nearly excluded Dalits, Tribals, OBCs and Minorities. Discrimination in academia has become the order of the day, be it the incidence of Rohit Vemula in Hyderabad Central University or JNU. Caste abhorrence and atrocities have led to the birth of organizations like Bhim Sena. What a shame! Lowest and dirtiest possible occupations were assigned to Dalits and for that also they are penalized. Can this way a country become great?

There are contradictions and without resolving them the struggle can't go in right direction. Do not expect from the Dalit and Adivasi Legislatures like MLAs and MPs who will fight for you because SCs/STs vote under the influence of political parties. A Dalit Legislature can't get votes of Dalit on his appeal, then who will care. If some legislatures try to be vocal for the cause, he will be side lined and others in the line will step in. It is right what Baba Saheb Ambedkar said that political power is the master key but he entered the congress and did a lot despite the fact master key was in the hand of Nehru Ji. The way the Patels and Jaats struggled for reservation without the help of politicians that is the way for us also and to wait to have master key by the time everything will be gone.

Executives and Legislatures can't finish the reservation and now that is being done through judiciary. The issue of reservation in promotion in UP ,MP and J&K has come in the Supreme Court . So far there was a danger in reservation in promotion but now supreme court is posing other dangerous game to apply creamy layer in SC/ST by citing example that a driver and a judge cannot be equal. The fact is that a judge or driver if they belong to same caste are equal but lower caste judge cannot be equal to upper caste judges. A driver lives in society not on car steering and judge in the files of courts.

The All India Confederation of SC/ST Organization (Parisangh) was founded in 1997 to oppose 5 anti-reservation orders and due to it's struggle 3 constitutional amendments were made. It fought for reservation for OBC in higher education. It's Bahujan Lokpal Bill led to the provision of reservation in Lokpal. The Parisangh defended reservation in promotion case (Nagraj) in Supreme Court in the year 2006 by hiring a private lawyer through government for a amour of 40 Lakhs. Dr. Udit Raj MP succeeded in introducing the private member bill for reservation in Private Sector in the Parliament, but due to lack of mass moment unlike Jaats and Patels, it has not progressed further. The Parisangh is the only organization which takes up day to day problems of SC/ST employees in the country. Lakhs of Dalits adopted Buddhism under it's banner on November 4, 2001. Is there any other organization in the country which has fought for ideological and constitutional rights. There are organizations who garner support by sowing the enemy, but they never jump into battle field. We say that if there is any other better organization than us, then support that otherwise rise above the caste and ego and join the rally on 4th December'17 at Ramleela Ground New Delhi at 11 AM. Remember the house number at a place is the only strength and go on doing lakhs of meetings here and there , will not help.

By: Om Prakash Singhmar, Parmendra, Devi Singh Rana, N.D. Ram, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj (Delhi), Sushil Kamal, Niraj Chak, Raj Kumar (U.P.), Sidharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, Archana Bhoyar, Sunil Jode (Maharashtra), S.P. Jaravata (Haryana), Tarsem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Vishram Meena, M.L. Rasu, Mukesh Meena (Rajsthan), Vijay Raj Ahirwar, Heera Lal (Uttarakhand), Alekh Mallick, D.K. Behera (Odisha), Paramhans Prasad, Narender Chaudhary, Vipin Toppo (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujrat), S.Karuppaiah, P.N. Perumal (Tamilnadu), Raman Bala Krishanan (Kerala), Madhu Chandra, Rev Langhu Hillery A. (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathod (Telangana), Ch. Das (A.P.), Harsh Meshram, Pradeep Sukhadeve (C.G.), P. Bala (W.B.), Madhusudan Kumar, Wilfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan (Bihar), J.Sreenivasulu (Karnataka), Sitaram Bansal, Nihal Singh Nihalta (H.P), Pradeep Basfore (Assam)

परिसंघ की बेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्य बने एवं सहयोग राशि भेजें

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की बेबसाइट www.aiparisangh.com पर अब ऑनलाइन सदस्यता एवं डोनेशन का प्रावधान कर दिया गया है। बेबसाइट पर जाकर कोई भी सदस्यता शुल्क की ऑनलाइन पेमेंट करके वार्षिक एवं आजीवन सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन डोनेशन भी किया जा सकता है। इस पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि सभी माध्यमों से पेमेंट की जा सकती है। अब कोशिश रहे कि ज्यादातर ऑनलाइन ही किया जाए, फिर भी यदि सदस्यता फार्म और डोनेशन की रसीदें छपी हुई चाहिए तो राष्ट्रीय कार्यालय में सुमित मो . 9868978306 से सम्पर्क किया जा सकता है।

परिसंघ के पदाधिकारियों से निवेदन है कि प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएं। यदि प्रदेश या जिले स्तर के पदाधिकारी अन्य लोगों को सदस्य बना रहे हैं तो वे फार्म में रेफर्ड बाई के कॉलम में अपना नाम अवश्य लिखें, इससे राष्ट्रीय कार्यालय को पता लग सकेगा कि किस पदाधिकारी द्वारा कितना ऑनलाइन डोनेशन कराया गया है और उनके माध्यम से कितने सदस्य बनाए गए हैं। इसके अलावा बेबसाइट पर परिसंघ का संक्षिप्त परिचय, राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिचय के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों के फोटो के साथ पता एवं मोबाइल नंबर भी दिया गया है, (http://aiparisangh.com/office-bearers/) ताकि जो लोग अलग-अलग प्रदेशों से बेबसाइट देखें उन्हें पता लग सके कि उस प्रदेश के किस पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा 'वॉयस ऑफ बुद्धा' भी बेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।

टीपू सुल्तान ने दलित महिलाओं को दिया ऐसा अधिकार, जिसका एहसान कोई नहीं चुका सकता है

कोई भी राजा हो क्या वह अन्याय इसलिए ना देखे और दंड ना दे कि यह अन्यायी उसके धर्म का नहीं और इस कारण से भविष्य में उस पर अन्य धर्मों के उपर किये अत्याचार के लिए गालियाँ दी जाएंगी? संघी और वाम इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को लेकर थोड़ा बड़ा दिल दिखाया पर अब टीपू सुल्तान को भी विवादित करने का प्रयास किया गया और औरंगजेब के जैसा बनाने का प्रयास किया गया, इतिहासकार टीपू सुल्तान के प्रति इस लिए झूठ न लिख सके क्योंकि टीपू सुल्तान का सारा इतिहास बहुत करीब के दिनों का है और यह तथ्य और सबूत है कि वह अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए और अपनी पूरी सल्तनत बर्बाद कर दी। दरअसल उनको बदनाम भी केवल सवर्ण कर रहे हैं, हकीकत यह है कि यदि इस देश के इतिहास को यदि निष्पक्ष रूप से लिख दिया जाए तो आज अचानक पैदा हो गये बड़े-बड़े महापुरुष नंगे हो जाएँ और जिन्हें खलनायक बनाया जा रहा है वह देश के महापुरुष हो जाएँ।

राजाओं की साम्राज्यवाद के कारणों से हुई लड़ाईयों को हिन्दू मुस्लिम की लड़ाई की तरह से अब प्रस्तुत किया जा रहा है और लडाई में मरने वाले सैनिकों को गिन गिन कर बताया जा रहा है कि इतने वध उस मुस्लिम शासक ने किये जैसे हिन्दू राजाओं ने युद्ध में विरोधी सेनाओं का धर्म देखकर ही मारा हो कि केवल मुस्लिम सैनिक मारें जाएँ हिन्दू सैनिकों को कोई नुकसान न हो चाहे विरोधी सेना का ही क्यों न हो तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ पर अब ऐसा ही किया जा रहा है। ब्रिटेन की नेशनल आर्मी म्यूजियम ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले 20 सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट बनाई है जिसमें केवल दो भारतीय योद्धाओं को ही इसमें जगह दी गई है।

नेशनल आर्मी म्यूजियम के आलेख के अनुसार टीपू सुल्तान अपनी फौज को यूरोपियन तकनीक के साथ ट्रेनिंग देने में विश्वास रखते थे। टीपू विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखते थे और उनके मिसाइल अंग्रेजों के मिसाइल से ज्यादा उन्नत थे, जिनकी मारक क्षमता दो किलोमीटर तक थी। जो अंग्रेज टीपू से इतना घबराते थे उनके बनाए झूठे इतिहास को दिखाकर संघ के लोग टिपू का विरोध कर रहे हैं। सच यह है कि विरोध कर रहे ऐसे लोग ही भारत के निष्पक्ष इतिहास के लिखने पर नंगे हो जाएँगे क्योंकि यही हर दौर में अत्याचारी रहे हैं और इसी अत्याचार को करने के लिये इन लोगों ने टीपू से अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजो का साथ दिया । त्रावणकोर के सवर्ण महाराजा, मराठे और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के सबसे बड़े मित्र थे जो चारों ने मिलकर एक अकेले टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया जिससे इनकी ऐय्याशियाँ चलती रहें देश जाए भाड़ में, चाहे इस पर अंग्रेजों का राज हो या राक्षसों का।

दरअसल जो ब्राम्हणों की हत्याएं करने का आरोप टीपू सुल्तान पर है वह त्रावणकोर राज्य में है जहाँ का ब्राम्हण राजा एक ऐय्याश और निरंकुश राजा था और उसके जुल्मों से वहाँ की जनता से छुटकारा दिलाने के लिए टीपू ने उसपर आक्रमण किया और युद्ध में त्रावणकोर की सेना में शामिल ब्राम्हण मारे गये। और अंततः राजा को वहाँ की दलित महिलाओं को न्याय देना पड़ा केरल के त्रावणकोर इलाके, खास तौर पर वहां की महिलाओं के लिए 26 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1859 में वहां के महाराजा ने दलित औरतों को शरीर के ऊपरी भाग पर कपड़े पहनने की इजाजत दी। इस परंपरा की चर्चा में खास तौर पर निचली जाति नादर की स्त्रियों का जिक्र होता है क्योंकि अपने वस्त्र पहनने के हक के लिए उन्होंने ही सबसे पहले विरोध जताया और जिनको हक दिलाने के लिए टीपू सुल्तान ने उस राज्य पर आक्रमण किया। दरअसल उस समय न सिर्फ पिछड़ी और दलित बल्कि नंबूदिरी ब्राहमण और क्षत्रिय नायर जैसी जातियों की औरतों पर भी शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने से रोकने के कई नियम थे। नंबूदिरी औरतों को घर के भीतर ऊपरी शरीर को खुला रखना पड़ता था। वे घर से बाहर निकलते समय ही अपना सीना ढक सकती थीं। लेकिन मंदिर में उन्हें ऊपरी वस्त्र खोलकर ही जाना होता था। नायर औरतों को ब्राह्मण पुरुषों के सामने अपना वक्ष खुला रखना होता था। सबसे बुरी स्थिति दलित औरतों की थी जिन्हें कहीं भी अंगवस्त्र पहनने की मनाही थी। पहनने पर उन्हें सजा भी हो जाती थी। एक घटना बताई जाती है जिसमें एक दलित जाति की महिला अपना सीना ढक कर महल में आई तो रानी अत्तिंगल ने उसके स्तन कटवा देने का आदेश दे डाला। इस अपमानजनक रिवाज के खिलाफ 19 वीं सदी के शुरू में आवाजें उठनी शुरू हुईं। 18 वीं सदी के अंत और 19 वीं सदी के शुरू में केरल से कई मजदूर, खासकर नादन जाति के लोग, चाय बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका चले गए। बेहतर आर्थिक स्थिति, धर्म बदल कर ईसाई बन जाने और यूरोपीय असर की वजह से इनमें जागरूकता ज्यादा थी और ये औरतें अपने शरीर को पूरा ढकने लगी थीं। धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बन जाने वाली नादर महिलाओं ने भी इस प्रगतिशील कदम को अपनाया।

इस तरह महिलाएं अक्सर इस सामाजिक प्रतिबंध को अनदेखा कर सम्मानजनक जीवन पाने की कोशिश करती रहीं। यह कुलीन मर्दों को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसी महिलाओं पर हिंसक हमले होने लगे। जो भी इस नियम की अहेलना करती उसे सरे बाजार अपने ऊपरी वस्त्र उतारने को मजबूर किया जाता। दलित औरतों को छूना न पड़े इसके लिए सवर्ण पुरुष लंबे डंडे के सिरे पर छुरी बांध लेते और किसी महिला को ब्लाउज या कंचुकी पहना देखते तो उसे दूर से ही छुरी से फाड़ देते। यहां तक कि वे औरतों को इस हाल में रस्सी से बांध कर सरे आम पेड़ पर लटका देते ताकि दूसरी औरतें ऐसा करते डरें। 1814 में त्रावणकोर के अंग्रेजों के चमचे दीवान कर्नल मुनरो ने आदेश निकलवाया कि ईसाई नादन और नादर महिलाएं ब्लाउज पहन सकती हैं। लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। उच्च सवर्ण के पुरुष इस आदेश के बावजूद लगातार महिलाओं को अपनी ताकत और असर के सहारे इस शर्मनाक अवस्था की ओर धकेलते रहे।आठ साल बाद फिर ऐसा ही आदेश निकाला गया। एक तरफ शर्मनाक स्थिति से उबरने की चेतना का जागना और दूसरी तरफ समर्थन में अंग्रेजी सरकार का आदेश। और ज्यादा महिलाओं ने शालीन कपड़े पहनने शुरू कर दिए।

इधर उच्च वर्ग के पुरुषों का प्रतिरोध भी उतना ही तीखा हो गया। एक घटना बताई जाती है कि नादर ईसाई महिलाओं का एक दल निचली अदालत में ऐसे ही एक मामले में गवाही देने पहुंचा। उन्हें दीवान मुनरो की आंखों के सामने अदालत के दरवाजे पर अपने अंग वस्त्र उतार कर रख देने पड़े। तभी वे भीतर जा पाईं। संघर्ष लगातार बढ़ रहा था और उसका हिंसक प्रतिरोध भी।सवर्णों के अलावा राजा खुद भी परंपरा निभाने के पक्ष में था। क्यों न होता ? आदेश था कि महल से मंदिर तक राजा की सवारी निकले तो रास्ते पर दोनों ओर नीची दलित जातियों की अर्धनग्न कुंवारी महिलाएं फूल बरसाती हुई खड़ी रहें। उस रास्ते के घरों के छज्जों पर भी राजा के स्वागत में औरतों को खड़ा रखा जाता था। राजा और उसके काफिले के सभी पुरुष इन दृश्यों का भरपूर आनंद लेते थे। आखिर 1829 में इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सवर्ण पुरुषों की लगातार नाराजगी के कारण राजा ने आदेश निकलवा दिया कि किसी भी दलित जाति की औरत अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक नहीं सकती। अब तक ईसाई औरतों को जो थोड़ा समर्थन दीवान के आदेशों से मिल रहा था, वह भी खत्म हो गया। अब हिंदू-ईसाई सभी वंचित महिलाएं एक हो गईं और उनके विरोध की ताकत बढ़ गई। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़ों में बाहर निकलने लगीं। इस पूरे आंदोलन का सीधा संबंध भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास से भी है। टीपू सुल्तान ने इसी अन्याय को समाप्त करने के लिए त्रावणकोर पर आक्रमण किया जिससे त्रावणकोर की सेना के तमाम लोग मारे गये जिसे आज ब्राम्हणों के वध के रूप में बताकर उनका विरोध किया जा रहा है उसी युद्ध में विरोधियों ने ऊंची जातियों के लोगों दुकानों और सामान को लूटना शुरू कर दिया। राज्य में शांति पूरी तरह भंग हो गई। दूसरी तरफ नारायण गुरु और अन्य सामाजिक, धार्मिक गुरुओं ने भी इस सामाजिक रुढ़ि का विरोध किया और अंततः 26 जुलाई 1859 को वहाँ के राजा ने दलित औरतों को स्तन ढकने की अनुमति प्रदान की। टीपू सुल्तान से वही खीज आज निकाली जा रही है। जरा सोचिएगा कि त्रावणकोर का राजा कोई मुस्लिम होता और दलितों के साथ ऐसा व्यवहार होता तो आज क्या स्थिति होती और यदि टीपू कोई दीपू होते तो ?

http://alivereport-com/tipu&sltan&gaive&right&to&dalit/

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

How did Hindus become Hindu and why Hindutva is not Hinduism

Devdan Chaudhuri

May we never hate each other.
The Katha Upanishad

The aim of this essay is to recover the true history and real meaning of key words, which have got muddled in the time of aggressive political and cultural propaganda.

How did Hindus become Hindu

It was the imperial British who demarcated on basis of religious beliefs - before that all major religious beliefs and practices, which originated in India, were termed together as Hindu - a word coined by the Persians to denote the land beyond the Sindhu or Indus river - after whom India has been named. The name Indica has been used by the Greeks to name India since the time of Herodotus and Megasthenes. Two works with the same title Indica - by Megasthenes and Arrian - described the Indian subcontinent. So the name of India got linked to the Indus River. The Persians followed the Greeks and named India after the river. But they followed the original Sanskrit name for Indus, and derived Hindu from Sindhu. In old Persian, "s" sounded like "h".So Hindu originally had a geographical connotation - from the Persian perspective - to denote "the land beyond the Sindhu"; the term wasn't coined to denote any religious meaning. The suffix "stan" - indicative of a geographical place - was added to form "Hindustan".

Sindhu in Sankrit also means river. India is that ancient river which is flowing since 5,500 years, or according to a recent archaeological discovery that happened in 2016, for 8,000 years.

That's why the word "Hindu" doesn't appear in the four Vedas, the Upanishads and the Buddhist scriptures. Even Adi Shankaracharya - who is known to have revived "Hinduism" in the 8th century after centuries of Buddhism - didn't have the word "Hindu" in his consciousness or vocabulary. He introduced the esoteric "Advaita" philosophy for the learned, while he simultaneously revived the worship of gods and goddesses for the masses.

Adi Shankaracharya also established the famous four peethas at Sringeri (South), Joshimath (North), Puri (East) and Dwarka (West). But he never used the word "Hindu" in any of his works of philosophy, commentary and spiritual poetry. But Buddhism didn't completely vanish from India. The Buddhist Pala dynasty ruled Eastern India - including Vanga - from 750 CE to 1174 CE during which the proto-Bengali language was developed along with the early "Bengali" culture.

The word "Hindu" doesn't appear in any ancient text of Sanatan Dharma - of all sub-religions and sub-cultures - before few Sanskrit texts started to use the word after 12th century. The various traditions used their philosophical and spiritual practices such as Vaishnavs, Shakta, Mahayana, Vajrayana, Advaita etc - to identify themselves. But no one called themselves Hindus. The Punjab region - Sapta Sindhava of the Vedas - has been called Hapta Hindu in Zend Avesta. A 6 BCE stone inscription of Persian King Darius I mentioned the land of Hi(n)dush - referred to North-Western India. The people of India were also referred as Hinduvan and Hindavi in the 8th century Persian text Chachnama. As pointed out earlier, the word "Hindu" is an ethnographic geographical word and didn't denote any religion. Al-Biruni's 11th century text Tarikh Al-Hind and also the texts of the Delhi Sultanate used the word "Hindu" to denote all non-Islamic people of India, and it remained ambiguous about whether Hindu denoted a region or a religion.

In the late 12th century, Prithviraj Raso by Chanda Bardai - that some scholars say was written later than 1192 - documented the defeat of Prithviraj Chauhan at the hands of Muhammad Ghori. That text is full of references to "Hindus" and "Turks". Here as well geographical meaning was used - it was a battle between "Hindus and Turks"; not Hindus and Muslims. The Indian invaders didn't come from Persia - the seat of Islamic high culture represented by modern day Iran - but they came from Central Asia and they were mostly Turks. The main religion of ancient Persia was Zoroastrianism. That was transformed by the Arab Conquest of Persia in 651 CE that expanded the Islamic Caliphate. King Darius I of the Zoroastrian Persia annexed parts of the Indus Valley in the north in 515 BCE, when the rest of ancient India was dominated by sixteen Mahajanapadas (great countries in Sanskrit) that included Magadha in the East - from where the Maurya and the Gupta Empires evolved and spread.

The Muslim Persian never tried to conquer India throughout its history. They never sent out an army towards Hind to annexe it with the Persian Empire and their scholars translated countless Sanskrit texts into Persian. So what is being viewed as "Muslim invasions" in present India in context of our history wasn't viewed as such in the medieval times of the invasions. The invaders were Central Asian Turkish warriors who were exceptionally skilled as horsemen. The first Mughal emperor Babur was a Central Asian Uzbeg. He was born in Andijan, Timurid Empire that is present day Uzbekistan. Even the Lodhi Sultanate Dynasty that Babur dethroned in Delhi originated from Afghan Pastun dynasty that was ruling North India since 1451. Muhammad of Ghazni, Muhammad Ghori and the Khilji dynasty - all originated from modern-day Afghanistan.

One has to keep in mind that the great empires of ancient India - such as the Mauryas and the Guptas - had extended beyond Afghanistan into Central Asia. Many of the Turks and Afghans who are now seen as "invaders into India" came from regions which were once part of the ancient empires of India.

The Persian "Hindu" slowly caught on among the people of India and they started to use that word to denote the difference between them and the Turks. Certain 16th-18th century Bengali Gaudiya Vaishnava texts started to use the word Hindu to contrast themselves with Yavanas (foreigners).

Chaitanya Charitamrita (16th century) and Bhakta Mela (17th century) - both in Bengali - used the phrase "Hindu dharma".

There are countless more examples. But the essential truth is that the people of India started to think themselves to be "Hindus" slowly over several centuries, after 12th century. This happened because of the Central Asian invasions that slowly popularised the Persian word among the populace. And the Imperial British added "ism" to Hindu in the early 19th century in order to execute its divide and rule strategy. All the three words: Hindus, Hindustan and Hinduism have no connection with ancient India, prior to 12th century. They began to get accepted gradually after 16th century by a larger populace. The recent DNA genealogy studies - from multiple sources - suggest: India has been populated primarily by three waves of ancient migrations. The last two waves from Central Asia, Caucus region and southern Siberia - around 12,000-15,000 years and 4,500-3,500 years ago - have given birth to India of now, in terms of "Hindu" population. Hindus are also the descendents of "invaders" into India; our world has been formed by migrations, and continues to be formed by migrations. But theHindutav ideology thinks India as a "pure land" for "pure Hindus". The ideology staunchly identifies with the three crucial words - "Hindu" and "Hindustan" coined by the Persians and "Hinduism" coined by the British - which are at the heart of its nationalistic narrative and worldview.

The three words - Hindu, Hindustan and Hinduism - were coined and popularised by Muslims and Christians - whom the Hindutva ideology identifies as "invaders".

The irony of this truth is astonishing

All the diverse philosophical traditions and the sub-traditions which originated in India are part of Sanatan Dharma that translates to "Eternal Law" or "Eternal Way of Things" or "Eternal Order". What are now called Hinduism, Buddhism or Jainism were the sub-cultures (with sub-sub-cultures) within the larger culture of Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has to be seen like a Great Wheel whose spokes are the diverse thoughts and belief systems which originated in India. Most of the major systems also imbibed aspects from the other systems of thoughts - ideas were mixed with other ideas to create more ideas. So the flow of Sanatan Dharma over time was like a braided stream. Plurality and syncretism were the essential part of Sanatan Dharma; this is reflected in the diversity of modern India. S Radhakrishnan's Indian Philosophy and Surendranath Dasgupta's A History of Indian Philosophy record the progression of all the major schools of thought which have shaped our history and culture. All the traditions and sub-traditions of all the religions under Sanatan Dharma stem from the major schools of Indian thought: the Vedas, the Upanishads, Buddhism, Jainism, Samkhyas, Advaita, Kashmir Shaivism and so on. They have got mingled with myths, legends, folklore, epic literature, passage of history and regional propensities to produce the diversity of religious and spiritual practices of India. So where does Hindutva fit within this scheme of things? From where did the word come into our consciousness?

Hindutva is not Hinduism

I have observed that books which have been written while the author is incarcerated tend to have a lasting impact in some sphere or the other. In 1923, while being incarcerated in Ratnagiri, VD Savarkar wrote his manifestoEssential of Hindutva. He coined the word Hindutva to frame his far-right political philosophy that uses nationalism and religious identity. Hindutva was ideated by Savarkar, not the spiritual sages of India. In the essay Hindutva: Who is a Hindu? Savarkar himself wrote, "Hindutva is not identical with what is vaguely indicated by the term Hinduism." His aim was the political mobilisation of all those with "Hindu" identity to form a nation of militant nationalists. By this time Savarkar was already a political person. In 1915, he had founded the right wing political party Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha. Dr KB Hedgewar read Savarkar's Essentials of Hindutva and was greatly inspired by the ideas. He severed his association with Indian National Congress and founded the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) in 1925. The Sangh Parivar started its journey when Hindu Mahasabha joined forces with RSS, and the Parivar adopted Savarkar's Hindutva to frame their essential far-right ideology that was also influenced by MS Golwalkar - the second sarsanghchalak or the second supreme leader of the RSS.

So Hindutva took birth as a political ideology and has little connection with the esoteric philosophical and spiritual ideals of Hinduism/Sanatan Dharma. It has always linked itself with patriarchal conservatism and ritualistic religion which they framed as "Hindu culture" and "Indian culture" while neglecting the plural and secular traditions of the broader and more diverse Hinduism/Sanatan Dharma.

The RSS also campaigned for Manusmriti as the Indian Constitution. Its inherent ultra-orthodox worldview always opposed liberal and progressive principles. They still dream to alter the Indian Constitution and change the Indian Tricolour to saffron.They also tend to think that the "Hindi-Hindustani" version of Hinduism is superior to the other kinds of Hinduism that are practised, especially in the South and Eastern India. They look down upon plurality as a sort of "religious and cultural" distortion. India never had a single all-powerful Church-like organisation to define the practices of Hinduism/Sanatan Dharma. This allowed multiple orthodox and unorthodox traditions and sub-traditions to take birth and flourish in India.

Respecting the freedom of the human spirit to seek, interpret, develop and pursue religious and spiritual activities as per one's own will and preference is an unsung hallmark of Indian civilisation. Plurality is not only the reality of modern of India, but it is also the essential "civilisational spirit" of our land.

In reality, when one looks behind the symbolisms, tokenisms and propaganda, one can assess that the ideals and principles of "Hindu Rashtra" resemble Hindutva Rashtra. More than "Hindu" interests, they represent Hindutva interest. Looking at our times, I am not sure, whether the Hindutva leaders and supporters believe in any of the prime concepts of Hinduism/Sanatan Dharma: truth, non-violence and karma. So one shouldn't confuse Hindutva with Hinduism/Sanatan Dharma; Hindutva is not a religious idea, but a far-right political ideology, just as Zionism is the far right political ideology of Judaism. The essential aim of any political ideology is to seek political power. The far right ideologies tend to exploit religion in a way that other moderate, liberal and progressive ideologies don't. By supporting or opposing Hindutva, one doesn't necessarily support or oppose Hinduism. By supporting or opposing the government, one doesn't necessarily support or oppose India.

Democracy gives the power to the people to rightfully oppose those who are in power; when this power of the people is diluted, then democracy turns into anti-democratic authoritarianism.

The government is not the nation; neither Hindutva is Hinduism.

The "politically-motivated" practice to call those who oppose the BJP government or the Hindutva ideology as "anti-nationals" and "anti-Hindus" is absurd. It's a manufactured polarisation and a psychological operation to divide people for the sake of political power. The "non-Hindutva Hindus" in our country are not "lesser Hindus" as the far-right would want their supporters to believe. The "non-Hindutva Hindus" are being derided as "sickulars", "libtards", "leftists" and so on. The Hindutva brigade is aggressively fighting the fellow citizens of one's own country and all the fellow Hindus who don't ascribe to its ideology. They have made "enemies" out of people, who simply don't agree with them. Hinduism/Sanatan Dharma is so vast and diverse, that no single definition of Hinduism can exist or be imposed upon India. That's why the Supreme Court of India defined Hinduism as a "way of life". The socio-cultural engineering mission of the Hindi-Hindustan-Hindutva brigade to "convert" all the Hindus of India with their practices, worldview and angst-ridden ideals, is doomed to flounder.

India is syncretic, multi-lingual, multi-cultural and diverse. When a single political party, religious organisation or a linguistic cultural group self-select themselves as the sole custodian of Hinduism, and wish to impose their ways on the rest, then they not only cause regional anxieties and stressful fissures in the wider social fabric, but they also violate the traditional "civilisational spirit" of our land. Theocracy-infused nationalism or 'theo-nationalism' that supplants humanism cannot also define patriotism in the 21st century when our collective progress is deeply inter-connected with the world. One also doesn't need to hate targeted groups of fellow citizens to display love for one's nation. Social, cultural and communal tensions in the time of a severe economic downturn will only peg back India. Those who are misunderstanding Hindutva as Hinduism and Hindutva nationalism as Indian nationalism should examine the nature of the ideals, values and actions which they are unwittingly supporting, and contrast them with the essential spiritual and philosophical principles of Hinduism/Sanatan Dharma.

https://www.dailyo.in/variety/hindu-hinduism-hindustan-hindutva/story/1/20120.html

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 23 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 16 to 31 October, 2017

Sample of the Poster for the comming Rally is being published. It is an ernest appeal ot the Confederation Leaders that they should get it printed on behalf of State And District Units and distribute.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya